ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 357-359

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-III, Issues-18, YEAR- Dec. -2020

बुन्देलखण्ड में पेयजल समस्या : चुनौतिया एवं संभावनाएं

डॉ0 आशा साहू Email : profashasahu07@gmail.com

Received- 28.11.2020, Revised- 01.12.2020, Accepted - 04.12.2020

सारांश– ***पेयजल एवं जीवन की आत्मनिर्भता के सन्दर्भ में "जल ही जीवन है" कहना अतिशयोक्ति नहीं है। भोजन के बिना व्यक्ति कुछ हफ्ते जीवित रह सकता है। परन्तु जल के अभाव में वह एक सप्ताह भी जीवित नहीं रह सकता। इतिहास साक्षी है कि विश्व का प्रत्येक देश विभिन्न नदियों, घाटियों की गोद में फला फूला है। वर्तमान समय में कृषि एवं औद्योगीकरण की बढती प्रवत्ति से जल की मांग निरन्तर बढती जा रही है। विश्व क्षेत्रफल के केवल 0.3 प्रतिशत भाग में शुद्ध जल है, अतः पानी की कमी इसके महत्व को और भी बढ़ा देती है। विकसशील देशों में पेयजल समस्या अधिक भयावह है क्योंकि इनकी तीन चौथाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उनके पास पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती है जो कि देश की एक गम्भीर समस्या है।***

कुंजीभूत शब्द–पेयजल, जीवन की आत्मनिर्भता,अतिशयोक्ति, औद्योगीकरण।

एसोसिएट प्रोफेसर– अर्थशास्त्र विभाग नेहरू पी. जी. कॉलेज, ललितपुर (उ0प्र0), भारत

अनुरूपी लेखक

अतः उपरोक्त सन्दर्भो से स्पश्ट है कि जल के अभाव में जीवन असम्भव है। यह जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पेयजल की समस्या उन क्षेत्रों में अधिक गम्भीर है जहा पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्र है। इसी तरह का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड संभाग है जहां पथरीली चट्टानों के कारण यह संकट स्थाई रूप ग्रहण करता जा रहा है। यहां निवास करने वाली जनता के पास स्वच्छ पेयजल के पर्याप्त साधन नहीं है। परन्तु इस समस्या को दूर करने में "हर घर जल" स्लोगन पर संचालित योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत शोधपत्र में वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र में अध्ययन हेतु उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड संभाग को लिया है। द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया है जो उपलब्ध सम्बद्ध प्रकाशित आलेखों, पुस्तकों से संकलित किए गये है। प्रस्तुत शोधपत्र के उद्देश्य निम्नलिखित है –

बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या का विभिन्न आयामों से सैद्धान्तिक पक्ष प्रस्तुत करना।

बुन्देलखण्ड में पेयजल समस्या से सम्बंधित किए विभिन्न सरकारी प्रयासों का अध्ययन करना।

बुन्देलखण्ड संभाग का परिचय एवं पेयजल की समस्या– उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड परिमंडल दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 29159 वर्ग किलो मीटर है। यहाँ पर कुल 96.82 लाख जनसंख्या (4.85 प्रतिशत) है, जिसमें से 77.33 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में तथा 22.67 प्रतिशत जनंसख्या नगरीय क्षेत्र में रहती है। उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड, झाँसी तथा चित्रकूटधाम मण्डल से मिल कर बना है। बुंदेलखण्ड में प्रमुख नदियाँ यमुना, बेतवा, धसान, जामनी, मन्दाकिनी, ओहन, गुन्ता, केन, वर्मा तथा चन्दावल है। बुंदेलखण्ड का अधिकांश भू–भाग असमतल पथरीला, पहाड़ी एव गहन बीहडों के भरपूर है। जहाँ उत्तरीय भाग यमुना और सहायक नदियों के दोआब से बना है वहीं पश्चिम से पूर्व की ओर का क्षेत्र विन्ध्याचल पहाड़ियों से घिरा है। बुन्देलखण्ड में प्रदेश के सात जनपद सम्मिलित हैं। बुन्देलखण्ड की आर्थिक स्थिति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2017–18 की सकल जिला आय अनुमानों के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कुल 4.9 प्रतिशत बुन्देलखण्ड का योगदान है जबकि इस क्षेत्र में प्रदेश की कुल जनसंख्या का 4.85 प्रतिशत निवास करता है बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश की भूमि का 1221 प्रतिशत सम्मिलित है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र का 60 प्रतिशत भाग पठारी और पहाड़ी है, जहां "धार वरियान युग" की प्राचीन चट्टाने है, जिन्हे "बुन्देलखण्ड बेसमेंट कामप्लेक्स" कहा जाता है। स्वच्छ पेयजल का स्वास्थ्य एवं काम करने की दशाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सतह का ढलाव अधिक होने के कारण वर्शा का जल बहुत कम अंश में भूगर्भ जल के रूप में भण्डारित होता है। कहीं–कहीं भूगर्भ जल खारा भी पाया जाता है। शुद्ध जल की आपूर्ति बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जटिल समस्या है। वर्षा ऋतु में बाढ़–जहाँ जान और माल की हानि करती है वही ग्रीष्म ऋतु में सूखा पड़ जाने पर यह मनुष्य व घरेलू पशुओं की मृत्यु का कारण बनती है। यहां लोगों को दूर से मीलों चलकर पेयजल भरकर लाना पड़ता है, जिससे

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-III, Issues-18, YEAR- Dec. -2020

उन्हे अनेक समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। भौगोलिक विभिन्नता के कारण इस परिमण्डल के जनपद झांसी, ललितपुर और बांदा सापेक्षतयः पेयजल संकट से अत्यधिक त्रस्त है। अतः जल संग्रहण की आधुनिक योजनाओं पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है।

बुन्देलखण्ड में पेयजल समस्या से सम्बंधित किए विभिन्न सरकारी प्रयास — संवैधानिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का दायित्व है किन्तु केंद्र सरकार भी इसमें बराबर भागीदारी निभा रही है। सरकार द्वारा जल आपूर्ति हेतु समय—समय पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बीस सूत्रीय कार्यक्रम में गांवों में साफ पीने का पानी सप्लाई करने को एक सूत्र में रखा गया। इसके अतिरिक्त त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम लागू किया गया। केंद्र सरकार ने पेयजल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन का गठन किया गया। पेयजल की महत्ता व शुद्ध पेयजल की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1981 से 1990 तक 10 वर्षो को अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल संभरण व स्वच्छता दशक घोषित किया। 1990—91 में राजीव गांधी पेयजल मिशन बनाया गया जिसमें 90 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। इसमें जहां पेयजल के कोई स्त्रोत नही है वहा पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया।

उपर्युक्त कार्यक्रमो के बाद भी पिछले कुछ दशकों से देश में जल की समस्या बनी हुई है। लोगो को पीने तक का पानी नहीं मिल पाता है। लेकिन भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना को लागू किया है, जिसके माध्यम से लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल दिया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना की शुरूआत की। इस योजना को हर घर जल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से ऐसे ग्रामीण एवं सुदूर इलाके, जहां जल की उचित व्यवस्था नहीं है वहां हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुचाने का इंतजाम किया जा रहा है ताकि किसी भी नागरिक को ऐसी समस्या का दोबारा सामना न करना पड़े।

जल जीवन मिशन से आज बुन्देलखण्ड क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। हर घर में शुद्ध पेयजल का सपना पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक घर में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे प्रारम्भ किया है। इसे बुन्देलखण्ड/विंध्य परियोजना के नाम से जाना जाता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपद झांसी, महोबा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा तथा चित्रकूट इस योजना से आच्छादित है। इन क्षेत्रों को 2022 तक लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 18.67 लाख घरों में पाइप लाइन से जोड़ा गया है। 57.62 लाख घरों में कार्य जारी है।

तालिका—1

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का जनपदवार विवरण

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	झांसी	[illegible]	[illegible]	111	[illegible]	[illegible]
2	महोबा	[illegible]	[illegible]	71	[illegible]	[illegible]
3	ललितपुर	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	जालौन	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	हमीरपुर	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	बांदा	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	चित्रकूट	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	योग	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

स्त्रोत— एस. डब्ल्यू. एस. एस., नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश, 2019.

तालिका—2

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रामीण पाइप पेयजल योजना द्वारा घरों में कनेक्शन

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	झांसी	10	1401
2	महोबा	5	11405
3	ललितपुर	17	8067
4	जालौन	5	5748
5	हमीरपुर	2	[illegible]
6	बांदा	2	12648
7	चित्रकूट	5	[illegible]
	योग	46	[illegible]

स्त्रोत— एस. डब्ल्यू. एस. एस., नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश, 2019.

तलिका से स्पश्ट है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ललितपुर जनपद में सबसे अधिक पेयजल परियोजनाएं 17 चलाई जा रही है। एवं बांदा जनपद में पाइप लाइन कनेक्शन द्वारा सबसे अधिक 12648 घर लाभान्वित हुए है।

बुन्देलखण्ड संभाग मे पेयजल समस्या के कारण— बुन्देलखण्ड संभाग में पेयजल समस्या के समाधान हेतु अनेकानेक प्रयास किए गए किन्तु अभी तक समस्या की गम्भीरता में कमी अवश्य आई पर समस्या समाप्त नहीं हुई, इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य विचारणीय है—

बुन्देलखण्ड में मूलतः भौगोलिक परिथितियों के कारण प्रायः पेयजल समस्या गंभीर हो जाती है।

यद्यपि सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों को हैण्डपम्प योजना द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। किंतु कहीं कहीं पर यह हैण्डपम्प भी वर्श भर जल आपूर्ति नहीं कर पाते।

संभाग में निरन्तर भूगर्भ जल दोहन बढता जा रहा है, यद्यपि पेयजलापूर्ति के लिए विभिन्न योजनाएं कियान्वित है। किंतु ये योजनाएं समस्सया समाधान में पूर्णतः सक्षम नहीं, क्योंकि कही व्यवस्था की कमी कही वितरण प्रणाली का दोशपूर्ण होना आदि।

जनसंख्या के आकार प्रकार में परिवर्तन के कारण भी पेयजल की मांग बढती है तो समस्या को गंभीर बनाती है।

PIF-7.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-III, Issues-18, YEAR- Dec. -2020

संभाग में पेयजल योजनाओं में लागत का स्तर ऊँचा है जिससे अन्य विकासात्मक कार्य प्रभावित होते है।

जलापूर्ति में समय चक्र की अनियमितता के कारण उपभोक्ता वर्ग का त्याग बढता है एवं अपना अमूल्य समय जल संचय में खर्च करता है।

निष्कर्ष– प्रस्तुत शोधपत्र के अध्ययन के पश्चात् कहा जा सकता है कि पेयजल समस्या एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यह समस्या यहां की भौगोलिक विभिन्नता के कारण पाई जाती है। यहां का अधिकांश भाग पथरीला व पठारी है। सरकार द्वारा जल आपूर्ति हेतु समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। परन्तु किसी न किसी कारण से वह इस क्षेत्र में सफल न हो सकी। इसी कड़ी के रूप में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना को लागू किया है, जिसके माध्यम से लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल दिया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा।

हर घर जल योजना के तहत हर घर में शुद्ध पेयजल का सपना पूरा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक घर में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे प्रारम्भ किया है। जनता को जल आपूर्ति देने के साथ ही लोगो को रोजगार देने का कार्य भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। संविदा के आधार पर प्लम्बर व इलेक्ट्रिशियन जैसे पद सृजित किए जा रहे है और स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है।

अतः जनता को पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का दायित्व है किन्तु केंद्र सरकार भी इसमें बराबर भागीदारी निभा रही है। इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं का संचालन करना इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि पेयजल जैसी अमूल्य वस्तु जनता को प्राप्त हो सके इसके लिए सरकार कृत संकल्प है।

सुझाव– अतः समस्या का बहुआयामी अध्ययन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि बुन्देलखण्ड संभाग में पेयजल व्यवस्था में सुधार एवं पुर्नगठन की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ सुझाव शोधपत्र में प्रस्तुत किए जा रहे है–

योजनाओं को वास्तविक ऑकड़ों पर आधारित कर धरातल पर उतारा जाए।

वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु नयी वैज्ञानिक एवं विकसित तकनीक का प्रयोग कर पुरानी योजनाओं का पुर्नगठन किया जाए।

पेयजल परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता एवं जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जाए एवं विद्युत व्यवधान न हो इसकी व्यवस्था की जाए। पाइप की टूट फूट एवं मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को सौप उसकी जबाबदेही तय की जाए।

ग्रामीण क्षेत्र में विकेंद्रीकृत छोटी–छोटी ग्राम समूह पेयजल योजनाएं बनाकर कियान्वित की जाए। प्रकृतिक एवं परम्परागत स्त्रोतों को भी संरक्षित किया जाए यदि इन्हें हम नश्ट होने से बचा सके तो समस्या को सुलझाना सम्भव होगा। जल बचत कर एवं अपव्यय को रोकने के लिए जन जागरूकता और जन सहभागिता आवश्यक है स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के प्रति सचेत रह जल संसाधन को प्रदूशण से बचाया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. रुद्रदत्त, सुन्दरम के. पी . एम. , भारतीय अर्थव्यवस्था, एसचंद्र एण्ड कंपनी लिमि., नई दिल्ली, 2005
2. सिंह आनन्द प्रकाश, सुनिश्चित रोजगार एवं ग्रामीण विकास, अमन प्रकाशन, सागर, 2000
3. राय, पारसनाथ, ''अनुसंधान परिचय'', 1989
4. एस. डब्ल्यू. एस. एस., नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश, 2019
5. बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश सामाजार्थिक परिदृश्य, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
6. उत्तर प्रदेश सरकार बजट 2019
7. समयान्तर मासिक पत्रिका 1995
8. योजना मासिक पत्रिका 2020

*****